Six people die in custody each day in India, Gujarat tops the list in between 2017-20

https://www.dnaindia.com/india/report-six-people-die-in-custody-each-day-in-india-gujarat-tops-the-list-in-between-2017-20-2951799

Amid furore over the custodial death in Chennai emerged another similar incident – this time from Mayurbhanj district of Odisha, where a youth suspected of jewellery theft died in police custody. Such horrible tales keep pouring in from different corners of the country almost every other day, even as the death of a businessman during a 'police raid' in UP's Gorakhpur and those of father-son duo Jeyaraj and Bennicks in Tamil Nadu's Thoothukudi are still fresh in public memory.

Tamil Nadu recorded 34 police custody deaths from 2017-20, one of the highest in the country. Gujarat (39), Maharashtra (33) and Madhya Pradesh (33) were the other states with maximum police custody deaths in the same period, as per NHRC data.

One of the major arguments for police reforms is the high number of custodial deaths in India. Recently, the Union Home ministry informed the Lok Sabha that the National Human Rights Commission (NHRC) recorded a whopping 2,152 deaths in judicial custody and 155 deaths in police custody in 2021-22 (till February 28). This translates to more than six custodial deaths in India every day!

UP accounted for the highest deaths in judicial custody (448) in 2021-22, while Maharashtra reported the highest deaths in police custody (29). In 2019, approximately five people died in custody every day, according to a report by New Delhi-based activist group National Campaign Against Torture.

As per NHRC data shared by the Union Home ministry, there were 1,840 judicial custody deaths in India in 2020-21; 1,584 in 2019-20; 1,797 in 2018-19; 1,636 in 2017-18 and 1,616 in 2016-17. Police custody deaths stood at 100 in 2020-21, 112 in 2019-20, 136 in 2018-19, 146 in 2017-18 and 145 in 2016-17.

Custody deaths have seen very few arrests and fewer convictions. And the role of NHRC has been equally disappointing. Of the total 11,419 custodial death cases from 2016-22, the rights body recommended compensation in only 1,184 cases, disciplinary action in a mere 21 cases (0.18 per cent), and prosecution in zero cases! From 2016-22, UP recorded the highest number of judicial custody deaths at 2,528. Maharashtra had the highest number of police custody deaths in the same period at 100.

In 2020, a Public Interest Litigation was filed seeking mandatory judicial inquiries into custodial deaths. The PIL pointed to a report by the National Crime Records Bureau which said that from 2005-17, out of 827 cases of death or disappearance from police custody, judicial inquiries were ordered in only 20 per cent of them.

The Supreme Court has also mandated that all police stations and investigation agencies must have CCTV cameras installed. But such orders are hardly followed.

As per reports, in the last two decades, 1,888 deaths in police custody have been reported across India. While 893 cases were registered against police personnel, only 358 policemen were formally accused, and a mere 26 policemen convicted.

NHRC की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर दिन 6 लोगों की हिरासत में मौत, नंबर एक पर यूपी

https://www.livehindustan.com/national/story-six-people-die-in-custody-each-day-in-india-up-tops-the-list-in-judicial-custody-between-2017-20-6465051.html

भारत में लंबे समय से पुलिस सुधार को लेकर चल रही चर्चा के बीच एक आंकड़ा जारी हुआ है जिसके मुताबिक भारत में हर रोज हिरासत में 6 लोगों की मौत होती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कमीशन (NHRC) का डाटा पेश किया जिसमें बताया गया है कि एक साल में कितने लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई। NHRC की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021-22 (फरवरी तक) के बीच न्यायिक हिरासत में 2,152 लोगों की मौत हुई जबकि 155 लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हुई। इसका मतलब ये हुआ कि हिरासत में हर रोज 6 लोगों की मौत हो रही है।

न्यायिक हिरासत में मौत के मामले में यूपी सबसे आगे है जहां 448 लोगों की न्यायिक हिरासत में मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 129 लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हुई है। नेशनल कैंपेन एगेंस्ट टॉर्चर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के आंकड़ों से तुलना की जाए तो 2019 में हर दिन 5 लोगों की मौत हिरासत में होती थी।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी NHRC डाटा के मुताबिक साल 2020-21 में 1,840 लोगों की न्यायिक हिरासत में मौत हुई। इसी तरह 2019-20 में 1,584 लोग, 2018-19 में 1,797 लोग, 2017-18 में 1,636 लोग और 2016-17 में 1616 लोगों की न्यायिक हिरासत में मौत हुई। वहीं पुलिस कस्टडी में हुई मौत को लेकर बात करें तो 2020-21 में 100 लोगों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई।

इसके अलावा 2019-20 में 112 लोग, 2018-19 में 136 लोग, 2017-18 में 146 लोग और 2016-17 में 145 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई। कुल मिलाकर 2016 से 2022 के बीच 11,419 लोगों की हिरासत में मौत हो चुकी है। हिरासत में हुई इन मौतों में से सिर्फ 1,184 मामलों में मुआवजे की सिफारिश की गई है और सिर्फ 21 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। 2016 से 2022 के बीच यूपी में सबसे ज्यादा 2,528 लोगों की न्यायिक हिरासत में मौत हुई है।

राजस्थान में आदिवासी युवती से बलात्कार मामला : एनएचआरसी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की

https://navbharattimes.indiatimes.com/india/nhrc-summons-report-from-senior-superintendent-of-police-in-case-of-rape-of-tribal-girl-in-rajasthan/articleshow/91452060.cms

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक आदिवासी युवती के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में राजस्थान के झालावाड़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से चार सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है।
मामले के अनुसार, यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी पुलिस अधिकारी जनवरी 2022 में पीड़िता की शिकायत पर उसके ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज मामले का जांच अधिकारी था।

शिकायतकर्ता गैर सरकारी संगठन 'इंडिजिनस लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' ने आयोग से तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

एनएचआरसी की वेबसाइट से मामले की मिली जानकारी के अनुसार, झालावाड़ जिले के भालटा पुलिस थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) जगदीश प्रसाद (59) पर दो मई की रात को 25 वर्षीय आदिवासी युवती के साथ बलात्कार करने का आरोप है।

चंदौली कांड में सियासतः अखिलेश ने कहा सरकार पर नहीं भरोसा, थानों में बढ़ा दलाली का सेंसेक्स
https://www.patrika.com/lucknow-news/akhilesh-yadav-on-chandauli-kand-said-yogi-government-not-trusted-7520119/
चंदौली जिले के मनराजपुर गांव में पुलिस दबिश के दौरान युवती की घटना से अब राजनीतिक गलियारों में सियासत शुरू हो गई। सपा प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को यूपी के चंदौली का दौरा किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने पुलिस की दबिश के दौरान जान गंवाने वाली लड़की के परिजनों से मुलाकात कर लड़की के पिता को सांत्वना दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी।

चंदौली-वाराणसी के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलने से पहले कहा कि यूपी में पुलिस थाने अराजकता के केंद्र बन गये हैं। अब सरकार की जांचों पर भी भरोसा नहीं रहा। दबिश के बहाने दबंगई करती है पुलिस। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस मनराजपुर गांव में किसी ना किसी की जान लेने की तैयारी में गई थी। अब अगर हाईकोर्ट के सीटिंग जज के अंदर जांच हो तो न्याय मिलने की उम्मीद है।

जाति के आधार पर होता है काम
चंदौली पहुंचे अखिलेश यादव ने पुलिस-प्रशासन और सरकार पर न केवल कटाक्ष किया बल्कि आरोप भी लगाए। कहा कि जो सरकार पुलिस को चुनाव जिताने में लगा दे, उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। थानों में दलाली का सेंसेक्स बढ़ रहा है। आरोप लगाते हुए बोले कि थानों में जाति के आधार पर काम हो रहा है। जनप्रतिनिधि के दबाव में यूपी सरकार यह कर रही है कि कब किसे फंसाना है। न्यायिक हिरासत में मौत, फर्जी मुठभेड़, महिला आयोग की नोटिस, एनएचआरसी की नोटिस मामले में प्रदेश पहले स्थान पर हो गया है।

क्या है चंदौली मामला
एक मई की दोपहर को चंदौली के सैयदराजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव में पुलिस जिला बदर के आरोपी कन्हैया यादव के घर दबिश डालने गई थी। आरोप के मुताबिक इस दबिश के दौरान कन्हैया यादव की पुत्री निशा यादव उर्फ गुड़िया की मौत हो गई थी। जिसकी मजिस्ट्रेट जांच हो रही है। इस मामले में राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई हैं। अखिलेश यादव से पहले भी कई अन्य पार्टियों के नेताओं मृतका के परिजनों से मुलाकात की। इस मामले में इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसवालों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है।

चेन्नई: अतिक्रमण विरोध अभियान ने घर तोड़ा-महिला रोड पर खाना बनाने को मजबूर
https://hindi.thequint.com/news/india/chennai-homeless-in-encroachment-drive-women-forced-to-cook-food-on-road-and-one-committed-suicide
चेन्नई में अतिक्रमण अभियान के दौरान एक महिला का घर तोड़े जाने के बाद उसने सड़कों पर खाना बनाना शुरू कर दिया. पीड़ित महिला ने बताया कि हमारे पास घर के सभी दस्तावेज हैं. बिना किसी सूचना के इसे तोड़ दिया गया. मैंने यहां सड़कों पर खाना बनान शुरू कर दिया है क्योंकि खाना बनाने के लिए और कोई जगह नहीं है.

प्रिया ने आगे बताया कि अधिकारियों का कहना है कि वे परिवार में केवल तीन सदस्यों को आवास योजना के तहत घर देंगे. उन्होंने हम सभी को बेघर कर दिया है. मेरी बीमार मां और मेरे बच्चे हैं. मैं यहां से नहीं जाऊंगी.

अतिक्रमण अभियान के विरोध में व्यक्ति ने किया आत्महत्या
दूसरी ओर चेन्नई में अतिक्रमण अभियान को तेज करने के विरोध में गोविंदसामी नगर के एलंगो स्ट्रीट निवासी 58 साल के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. जी. कन्नैयन के परिवार ने बताया है कि वह 90 फीसदी जल गए हैं और उन्हें सरकारी किलपौक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, श्री कन्नैयन के बेटे के सुरेश ने मानव अधिकारों के उल्लंघन में बेदखली का आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेने की अपील की

चेन्नई के अलावा, देश के कुछ हिस्सों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहे हैं. देश की राजधानी दिल्ली में भी दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, जो 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध का गवाह बना था.

तूल पकड़ गया चर्मशोधन इकाइयों को तोड़ने का मामला

https://www.jagran.com/uttar-pradesh/bagpat-baghpat-22698840.html

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर थाना दोघट के भड़ल में 85 चर्मशोधन इकाइयों के ध्वस्तीकरण का मामला तूल पकड़ गया। शोषित क्रांति दल के अध्यक्ष रविकांत ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित कर मुकदमा दर्ज नहीं करने पर आंदोलन करेंगे। सोमवार को बागपत में रविकांत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भड़ल में अनुसूचित जाति के लोग चर्मशोधन पुश्तैनी काम कर परिवार की रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। निजी जमीन पर चर्मशोधन इकाईयां थी। सात मई को प्रशासन और पुलिस ने बिना सूचना दिए व बिना नोटिस दिए और बिना आदेश दिखाए लाठीचार्ज कर बुलडोजर चलाकर 85 चर्मशोधन इकाई ध्वस्त की। कई लोगों के घर गिरा दिए और जेल भेज दिए हैं। पुलिस कर्मियों को निलंबन व अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने व जेल से रिहा करने की मांग की। तीन दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एससी-एसटी आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर न्याय मांगा जाएगा।

Tribal woman rape case in Raj: NHRC seeks action taken report from SSP

https://theprint.in/india/tribal-woman-rape-case-in-raj-nhrc-seeks-action-taken-report-from-ssp/949527/

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought an action taken report in four weeks from the senior superintendent of police of Jhalawar in Rajasthan in connection with the alleged rape of a young tribal woman by a police official. According to the proceedings of the case, it has been further alleged that the accused police official was the investigating officer of a case registered on complaint of the victim against her in-laws in January 2022

The complainant, an NGO, “Indigenous Lawyers Association of India (ILAI), in the instant case is seeking urgent intervention of the Commission in a matter wherein one 25-year-old tribal woman was allegedly raped by Assistant Sub Inspector (ASI) Jugdish Prasad (59 years) of Bhalta police station in Jhalawar district on the intervening night of 2.5.2022,” according to the proceedings accessed from the NHRC website. The complainant is seeking intervention of the Commission in the matter, it said. According to the proceedings, the action by the NHRC was taken on May 6.

“The Commission directs its registry to transmit the copy of complaint to the concerned authority calling for an action taken report within four weeks. The concerned authorities shall also intimate the Commission, if any, notice, order etc., has been received by him/them in the instant matter from the State Human Rights Commission,” the case proceedings read. “If yes, a copy of such order be also sent to the Commission within four weeks. Let a copy of the complaint be also transmitted to the Secretary of the concerned State Human Rights Commission, calling upon him to inform this Commission the date of cognizance, if any, taken at their end in the instant matter within four weeks,” it added.

The action taken report has been sought from SSP, Jhalawar, according to the proceedings. The accused police officer was arrested for allegedly raping the 25-year-old tribal woman in Jhalawar district, police had said on May 5. A case was lodged against the officer under Section 376 (2) (a) (i) (rape by police officer within designated police station limits) of the Indian Penal Code and the Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989, local officials had earlier said. PTI KND CK

PMK functionary, who immolated self against demolition drive succumbs

https://www.uniindia.com/story/PMK-functionary-who-immolated-self-against-demolition-drive-succumbs

A Pattali Makkal Katchi (PMK) functionary, who immolated himself yesterday to protest the eviction and demolition to remove encroachments in water bodies in the city, succumbed to burns on Monday. The demolition drive was carried out by the Water Resources Department and the Tamil Nadu Urban Housing Development Board at Govindasamy Nagar in RA.Puram area on the ground that the people have encroached areas near the Buckingham canal. In protest against, the PMK District Deputy Secretary G.Kanniah (58) attempted self-immolation yesterday afternoon. He suffered more than 90 per cent burns and was rushed to the Government Kilpauk Government Hospital, where he died without responding to the treatment today morning. As tension prevailed in the area following the immolation, the authorities have temporarily suspended the demolition drive, even as protest by the locals, which commenced last evening, continued for the second day today, opposing their eviction and demolition. They also hoisted black flags atop their houses to condemn the demolition. Alleging that the eviction was being done in violation of human rights, the deceased son K.Suresh, demanded action against the officials concerned and appealed to the National Human Rights Commission (NHRC) to take suo motu cognisance of the incident. While the government maintained that the eviction drive was being carried out as per the orders of the Supreme Court in a case filed by an individual to remove the encroachments, the residents alleged that successive state governments have failed to plead their case properly. The locals accused the government of expediting the demolition drive after coming to know that they were planning to approach the Supreme Court today with the help of an NGO. PMK Founder Dr.S.Ramadoss condoled the death of Kanniah and urged the State government to announce a solatium of Rs one crore and a government job for one of his family members. In a statement, he also demanded action against all those responsible for his death. Refusing to accept the government's stand that the demolition was being done on the basis of court orders, Ramadoss said there is no divergent view that water bodies should not be encroached. But several water bodies and Pallikaaranai marshland in Chennai were encroached by affluent people and big companies. The government, instead of evicting them, has been targetting the poorer sections, who could not raise their voice. It is not justified, he added. Meanwhile, a petition was filed by a NGO in the Apex Court seeking a stay on the demolition today. Following a request for an early hearing, the Court said it will take up the matter tomorrow, reports received here said. UNI GV 1642

Fight your own battles: A reality check for West Bengal as Amit Shah wraps up two-day state visit

https://www.financialexpress.com/india-news/fight-your-own-battles-a-reality-check-for-west-bengal-bengal-as-amit-shah-wraps-up-two-day-state-visit/2517720/

Union Home Minister Amit Shah, who wrapped up his two-day visit to West Bengal recently, is learnt to have conveyed in clear terms to the state unit of the Bharatiya Janata Party (BJP) that the fight against the Mamata Banerjee-led Trinamool Congress is political, and one that needs to be led by the state unit and not the Centre, sources privy to the developments told Financial Express Online. Shah's remarks, which came during a closed-door meeting with BJP leaders including party MPs and MLAs, appeared to be specifically aimed at asking the stumbling party unit to pull up its socks and gear up to take the fight to the TMC.

Shah's remarks came in the backdrop of repeated demands for imposing President's rule in the state in view of rising incidents of political violence and killings allegedly aimed at BJP workers, besides calls for probe by the Central Bureau of Investigation into the cases lodged against TMC leaders. This was Shah's first visit to the state following the party's loss in the 2021 assembly elections.

Speaking to Financial Express Online, party leaders said Shah's two-day visit to West Bengal was aimed at boosting the morale of the state workers and strengthening the party from the grassroots level ahead of the 2024 Lok Sabha and the 2026 assembly elections. Shah told the leaders that they will have to carry on the fight without any expectation despite the state machinery against them. Shah also told the state party leaders that BJP will win the next state election in West Bengal with a two-thirds majority.

Adani Wilmar Rating: Performance in Q4FY22 was a mixed bag

However, a top BJP leader refuted reports suggesting that Shah had frowned upon demands to impose President's rule in the state and the expedition of CBI cases in the state. "These four words such as Article 355, Article 356, Enforcement Directorate and CBI were not even uttered in the closed door meeting. However, Shah said that we will have to carry on with our organisational activities regardless of the adverse political situations and against a hostile state machinery."

"The BJP officially never wanted to impose President's rule in the state. We had only said that the time is ripe for the custodian of constitution to intervene due to the complete breakdown of constitutional machinery. The only person who officially wanted Article 355 in the state was Congress leader in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury," the leader added while maintaining that they had brought up the issue of police excesses such as not filing of FIRs and the breakdown of law and order.

On Friday, Shah's visit was marred by the hanging of a BJP youth leader Arjun Chowrasia, who was organising a bike rally in Kolkata to welcome the Home minister a

night before his death. Soon after, all ceremonies planned to welcome Shah were cancelled as both the Bengal BJP unit and Chowrasia's family alleged that he was murdered and called it another case of political violence by the ruling Trinamool Congress. Shah visited the family of the deceased and called for a CBI probe while asking the Bengal government a detailed report of his death.

BJP Bengal spokesperson and former MLA Samik Bhattacharya told Financial Express Online that Shah had urged the BJP leaders in the state not to bow down to political violence and keep on working to strengthen the organisational roots in the state. In a bid to encourage the BJP workers, Shah asked them to draw inspiration from his own political struggle. "From spending two years in exile to spending time in jail, I have suffered several blows, but the then Congress government at the Centre could never break my spirit," Shah told BJP leaders, according to Bhattacharya.

The BJP spokesperson, citing the National Human Rights Commission (NHRC) "Law of ruler, not rule of law" report on political violence tabled before the Calcutta High Court last year, alleged that BJP workers are being targeted by the state machinery at block levels. "If they're taking out protests on road, the cops either make them join TMC forcibly or if they refuse, the police file cases against them. On other occasions, they either end up getting murdered or their livelihoods snatched," he said.

This was Shah's first visit to Bengal after the party's 2021 electoral debacle. On asking why no prominent leader from the central BJP leadership had visited the state, a top BJP leader, who was also present at the closed door meeting, a BJP source said, " Amit Shah wanted to respect the people's mandate. But, after one year when he visited he said that the TMC hasn't changed a bit — in fact, things have taken a turn for the worse with atrocities increasing across the state. Shah said that the fight to establish law and order will now strengthen and he will visit more frequently."

On Shah's visit, BJP MLA and Bengal spokesperson Sreerupa Mitra Chaudhury told Financial Express Online that he interacted with leaders sitting in the audience and gave them a patient hearing, while thanking each one of them for being part of the political struggle in Bengal. "Amit Shah ji encouraged partymen to continue their political journey for the sake of peace, non-violence and in nation's interest. He said sacrifices of young souls like Arjun Chaurasia shall be remembered by the nation," said Chaudhury.

After the state assembly results, many TMC top leaders who had earlier jumped ship to join BJP like Mukul Roy and Sabyasachi Dutta, rejoined their old party. Following this, the party has been in a free fall in the state facing stiff challenges from other opposition parties like the Congress and the CPI(M) in the recently concluded civic body polls.

However, many in the BJP believe that cases of such leaders rejoining TMC may not be a bad thing for the party after all. "Style and body language of people who have come from TMC will not match ours. While some have adjusted, the others came with the mindset of creating internal division, getting a party ticket and carrying on with the loot by merely changing camps. With all these leaders like Mukul Roy gone, the BJP has

been strengthened, especially in those particular constituencies and the faith of the ground level workers restored," a party leader told Financial Express on condition of anonymity.

Custodial death in Odisha`s Mayurbhanj district: Six lives lost behind bars daily in India - An analysis

https://zeenews.india.com/india/custodial-death-in-odishas-mayurbhanj-district-six-lives-lost-behind-bars-daily-in-india-an-analysis-2461957.html

Amid furore over the custodial death in Chennai emerged another similar incident – this time from Mayurbhanj district of Odisha, where a youth suspected of jewellery theft died in police custody.

Such horrible tales keep pouring in from different corners of the country almost every other day, even as the death of a businessman during a 'police raid' in UP's Gorakhpur and those of father-son duo Jeyaraj and Bennicks in Tamil Nadu's Thoothukudi are still fresh in public memory.

Tamil Nadu recorded 34 police custody deaths from 2017-20, one of the highest in the country. Gujarat (39), Maharashtra (33) and Madhya Pradesh (33) were the other states with maximum police custody deaths in the same period, as per NHRC data.

One of the major arguments for police reforms is the high number of custodial deaths in India. Recently, the Union Home ministry informed the Lok Sabha that the National Human Rights Commission (NHRC) recorded a whopping 2,152 deaths in judicial custody and 155 deaths in police custody in 2021-22 (till February 28). This translates to more than six custodial deaths in India every day!

UP accounted for the highest deaths in judicial custody (448) in 2021-22, while Maharashtra reported the highest deaths in police custody (29). In 2019, approximately five people died in custody every day, according to a report by New Delhi-based activist group National Campaign Against Torture.

As per NHRC data shared by the Union Home ministry, there were 1,840 judicial custody deaths in India in 2020-21; 1,584 in 2019-20; 1,797 in 2018-19; 1,636 in 2017-18 and 1,616 in 2016-17. Police custody deaths stood at 100 in 2020-21, 112 in 2019-20, 136 in 2018-19, 146 in 2017-18 and 145 in 2016-17.

Custody deaths have seen very few arrests and fewer convictions. And the role of NHRC has been equally disappointing. Of the total 11,419 custodial death cases from 2016-22, the rights body recommended compensation in only 1,184 cases, disciplinary action in a mere 21 cases (0.18 per cent), and prosecution in zero cases! From 2016-22, UP recorded the highest number of judicial custody deaths at 2,528. Maharashtra had the highest number of police custody deaths in the same period at 100.

In 2020, a Public Interest Litigation was filed seeking mandatory judicial inquiries into custodial deaths. The PIL pointed to a report by the National Crime Records Bureau which said that from 2005-17, out of 827 cases of death or disappearance from police custody, judicial inquiries were ordered in only 20 per cent of them.

The Supreme Court has also mandated that all police stations and investigation agencies must have CCTV cameras installed. But such orders are hardly followed.

As per reports, in the last two decades, 1,888 deaths in police custody have been reported across India. While 893 cases were registered against police personnel, only 358 policemen were formally accused, and a mere 26 policemen convicted.

PUNJAB KESARI, Jammu, 10.5.2022
Page No. 10, Size:(13.07)cms X (18.63)cms.

13 वर्षीय बच्ची ने सुनाई खौफनाक कहानी

पहले चार लोगों ने किया 4 दिन तक गैंगरेप, फिर इंस्पैक्टर ने थाने में मिटाई हवस

लखनऊ, 9 मई (विशेष): उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। लड़की ने जो कहानी बयां की है, उससे पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ गए हैं।

पूरे मामले का खुलासा एक सप्ताह पहले 2 मई को उस वक्त हुआ जब चाइल्ड लाइन की टीम पीड़ित लड़की को उसकी मां के साथ लेकर एस.पी. के पास पहुंची। उसे पहली बार 22 अप्रैल को ललितपुर जिले में उसके घर से चार लोगों ने अगवा किया और चार दिन तक सामूहिक बलात्कार किया। जब वह शिकायत दर्ज कराने गई तो पाली थाने के थाना प्रभारी तिलकधारी सरोज ने 27 अप्रैल को उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। तीन दिन बाद उसे एक गैर-सरकारी संगठन को सौंप दिया गया।

तीन दिन तक नरक से गुजरी बच्ची : उससे बात करने वाले काऊंसलर के अनुसार बच्ची तीन दिन तक नरक से गुजरी थी। वह कहते हैं कि उस दोपहर जब दो पुलिस कर्मियों द्वारा उसे हमारे पास लाया गया, तो वह बहुत डरी और सहमी- सी लग रही थी। हमसे बात नहीं कर रही थी। एक बार जब पुलिस चली गई तो हमने उसे काऊंसलिंग के हिस्से के रूप में उकसाना शुरू किया।

तब वह खुलकर बात करने लगी। वह 22 अप्रैल से घटना के बारे में बताने लगी, जब चंदन, राजभान, महेंद्र चौरसिया और उसके एक चचेरे भाई ने उसका घर से अपहरण कर लिया और उसे भोपाल ले गए। लड़की ने काऊंसलर को बताया कि उनमें से किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक चारों आरोपियों ने किसी भी होटल में चैक-इन नहीं किया था क्योंकि वे लापता रहना चाहते थे।

पुल के नीचे बिताई रातें, खाने को चाउमिन और अंडे

काऊंसलर ने पीड़ित लड़की के हवाले से कहा कि दिन में वे रेलवे स्टेशन के पास सड़कों पर घूमते थे, और रातें एक पुल के नीचे बिताई जाती थीं, जहां आरोपी बारी-बारी से उसका बलात्कार करते थे, जबकि उनमें से एक पहरा देता था।

एन.जी.ओ. ने लड़की के हवाले से यह भी कहा कि एक अन्य आरोपी राजभान ने बंदूक ले रखी थी और उसे धमकाया जाता था कि अगर उसने झगड़ा किया तो उसके माता-पिता को जान से मार दिया जाएगा। पीड़ित लड़की ने चाइल्ड केयर वर्कर्स को बताया कि उनका भोजन चाउमिन और एक भयावह हालत में थी। अब वह केवल एक पुल, कुछ गलियों, ट्रेनों की आवाज और एक मस्जिद से अजान को याद करती है।

काऊंसलर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पहले ही ललितपुर में अपराध के दृश्यों की पहचान कर ली गई है।

एस.एच.ओ. का नाम लेती रही मासूम

काऊंसलर याद करते हैं कि मासूम पीड़ित लड़की ने एस.एच.ओ. सरोज का नाम लेने के लिए लगातार प्रयास किया। काऊंसलर ने कहा, एक दर्जन बार उसने मुझसे कहा कि एस.एच.ओ. ने उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन उसने कभी किसी अन्य पुलिसकर्मी

अनुभव का खुलासा करने के बाद वह आखिरकार सो गई। उसके काऊंसलर ने कहा कि तनावग्रस्त बच्चा शाम करीब छह बजे सोता है और सुबह सात बजे ही उठता है।

काउंसलर ने कहा कि उनके सौतेले पिता जो अनुसूचित जाति की पृष्ठभूमि से एक मजदूर हैं, ने कहा कि 1 मई को उनकी अंतिम मुलाकात एक भावनात्मक मामला था।

उन्होंने कहा कि उनके पास यह बताने के लिए चेहरा नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ था। 2 मई को, पीड़िता और उसके सलाहकारों ने पुलिस अधीक्षक से 90 मिनट तक मुलाकात की। अगले दो दिनों में पूरे थाने को निलंबित कर दिया गया। प्राथमिकी दर्ज की गई तथा सरोज व पांच संदिग्धों को

STATESMAN, Bhubaneswar, 10.5.2022
Page No. 2, Size:(11.76)cms X (15.80)cms.

NHRC petitioned in rape case

STATESMAN NEWS SERVICE
BHUBANESWAR, 9 MAY:

Himansu Shekhar Nayak ,a native of Solpata of Keonjhar district complaint before the NHRC demanding justice for a married woman who was sexually assaulted by a witch doctor for 79 days on the pretext of solving her martial dispute.

He requested the NHRC to direct the Chief Secretary of Odisha and SP of Balasore to provide Rs.15 lakh compensation to the victim within three weeks.

Accused Sk Toraff, a tantric had sexually assaulted a married woman for 79 days on the pretext of solving her marital dispute. The shocking incident came to light after the victim lodged an FIR with police on Friday accusing her husband and in-laws of forcing her to keep sexual relations with the tantric.

On April 28, the victim had managed to find the tantrik's cell phone in his absence and texted her parents about her plight. Her parents immediately took help from Moroda police and rescued her from Toraff's house the same day.

Police is in search of the tantric who has absconded.